14.23 hrs.

CONSTITUTION (TWENTY-THIRD AMENDMENT) BILL*

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRI MUTHYAL RAO): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India".

SHRI SHIVA CHANDRA JHA rose—

MR. CHAIRMAN: I remember the Hon. Speaker having told Shri Shiva Chandra Jha that on every Bill he wants to oppose it at the introduction stage. Normally, when a Bill is introduced from any side, whether it is a private Member's Bill or it is a Government Bill, the introduction is never opposed. But if the hon. Member is opposed to the very principle of the Bill, then he can speak for five minutes.

SHRI A. S. SAIGAL (Bilaspur): He is making it a habit to oppose the introduction of every Bill. This is not correct.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Yesterday, when the Hon. Speaker said that to Shri Shiva Chandra Jha, the hon. Members of the Opposition said that any Member in the House had a right to oppose a Bill at the introduction stage. I would submit that the Member's wisdom should not be judged by the Speaker. After all, we are all wise people here when we oppose a Bill either from this side or that side. Supposing a Bill is introduced from the centre, then what will happen?

श्री शिव जन्म सा (मघुबनी): सभापति जी, यह संविधान का 23 वां संशोधन विधेयक हमारे सामने पेश किया गया है । इसके सम्बन्ध में एक संवैधानिक ग्रापत्ति मैं ग्रापके सामने रखना चाहता हूं । इस में फाइनेन्सल मेमोरेण्डम है, जिसका मतलब यह है कि यह मनी-बिल हो जाता है । संविधान की धारा 110 को देखें, उसकी उपधारा (ए) से (एफ) के ग्रनुसार कन्सोलिडेटिड फण्ड से जो पैसा लिया जाता है, वह मनी-बिल हो जाता है । यह बिल, भले ही इसमें खर्च कम हो, लेकिन मनी-बिल हो जाता है । श्रव इसके पास करने के लिए संविधान की धारा 117 को पढ़ें, इसमें लिखा है—

"A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of article 110 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the President and a Bill making such provision shall not be introduced in the Council of States."

ग्रब प्रश्न यह है कि इस विधेयक को लेकर प्रेजिडेन्ट की रिक्मेन्डेशन कहां है। हा-लांकि ग्रब नो गिरी साहब प्रेजिडेन्ट हैं, लेकिन एक्टिंग-प्रेजिडेंट की रिक्मेन्डेशन भी इसमें कहीं नहीं है। इसलिये कास्टीचूशनली यह विधेयक ठीक नहीं है, मैं उसका विरोध करता हूं और चाहता हूं कि ग्राप पहले रिक्मेन्डेशन लेकर ग्रावें।

^{*}Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 21-8-69.

श्री मथु लिमये (मंगेर) : मझे वैधानिक श्रापत्ति है । इस बिल के दो हिस्से हैं । एक तो जो अनुसूचित जातियां हैं, जो हरिजन हैं. गिरिजन हैं या बनवासी लोग हैं, उनसे संबन्धित हैं, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है । मैं यह समझता हं इनके लिए रिजवेंशन वगैरह करना बिल्कुल मुनासब है । लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है बीस साल के बाद भी एंग्लो इण्डियन्स के लिए यह नामजदगी करने का क्या तुक है ? वे शैक्षणिक ग्रौर सामाजिक दृष्टि से पिछडे नहीं हैं. . . (व्यवधान) . . फ्रैंक साहब तो बड़े बैरिस्टर हैं वे तो अपनी बात कहें गे ही लेकिन मैं दो बातें ग्रापके सामने रखना चाहता हं। यह भी कानन है, सुश्रीम कोर्ट का फैसला है कि कांस्टीटयशन ग्रमेंडमेन्ट बिल भी कानन है । इसलिए फंडामेंटल राइटस का जो हिस्सा है उसके अनुसार कोई भी बिल होना चाहिए । अब मेरा आपमें निवेदन यह है कि हमारे संविधान की 14 और 15 धाराग्री में कहा है कि सभी नागरिकों ग्रीर व्यक्तियों को कानुन के सामने समान स्रधिकार रहेंगे ।...(**व्यवधान**)...मैं क्लाज 15 (4) भी पढ़ने वाला हं। में वेवकफी नहीं कर रहा हं। तो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए विशेष संरक्षण देने की बात को मैं स्वीकार करता हं। मेरी पार्टी का यह सिद्धांत है कि औरत हो, पिछड़े वर्गं के लोग हों, हरिजन, ग्रादिवासी, मसलमानों में जो पिछड़े हैं वे हों या सिखों में पिछड़े हए हों उनको साठ फीसदी जगह सेवाग्रो में देनी चाहिए । वह तो मेरी पार्टी का सिद्धांत है । लेकिन मैं केवल ऐंग्लो इण्डियन कम्यानिटी के बारे में कह रहा हूं कि वे शैक्षणिक दृष्टि से स्रीर सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग में नहीं आते हैं। आरप 15(4) को देखिए। इसमें जो छट है :

"Nothing in this article or in clause (2) of article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citi-

zens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.".

तो क्या फ्रैंक साहब यहां पर बताने की कोशिश करेंगे कि ऐंग्लो इण्डियन कम्यनिटी के सदस्य सामाजिक, शैक्षणिक श्रौर म्रार्थिक द्विट से पि**छ**ड़े वर्ग में म्राते हैं ? म्रगर वे ऐसा कहेंगे तो मेरा जो आक्षेप है उसको वापिस ले लंगा, वरना मेरी राय है कि स्रब बीस साल हो गए हैं, भ्रब उनको बिल्कुल समाज में मिल जाना चाहिए. जैसे समाज के दूसरे ग्रंग हैं, सामाजिक ग्रौर ग्रायिक द्प्टि से जो काफी ग्रागे बढ चुके हैं, एंग्लो इण्डियन भी उसी तरह से ग्रागे बढ़े हुए लोग हैं ग्राँर वह मिल-जलकर काम करेंगे तो फिर फैंक साहब को नामिनेट करने की क्यों जरूरत पडेगी। हो सकता है जबलपूर से वे जीत कर स्रायें, उसमें मूझे भी खुशी होगी । इतना ही मुझे कहना है।

THE MINISTER OF LAW AND G0-SOCIAL WELFARE (SHRI VINDA MENON): Regarding Shiva Chandra Jha's objection, is not a money Bill. The recommendation of the President under article 117 (3) has been obtained and Shri Shiva Chandra Jha took objection to the absence of the recommendation, but the recommendation is there.

Regarding Shri Madhu Limaye's objection, the Anglo-Indian community has been given the right of having certain seats reserved for them to be filled by nomination. Even in the Constitution itself article 331 says:

"Not withstanding anything in article 81, the President may, if he is of opinion that the Anglo-Indian community is not adequately represented in the House of the People, nominate not more than two members of that community to the House of the People.".

Initially this was for a period of ten years. It has been extended by another ten years, and the object of the present Bill is to give a further extension of a period of ten years. It already exists in the Constitution...

SHRI MADHU LIMAYE: So what?

SHRI GOVINDA MENON: If this is opposed to any of the Fundamental Rights guaranteed by the Constitution, I do concede that the law will be invalid, but it is not opposed to any of the Fundamental Rights guaranteed by the Constitution.

SHRI MADHU LIMAYE: Article 14

SHRI GOVINDA MENON: Article 14 is not the only Fundamental Right. There are others also like articles 15 and 16

SHRI MADHU LIMAYE: Yes; read out.

SHRI GOVINDA MENON:... and nothing done in order to protect special classes of people will go against the Fundamental Rights of the people.

श्री मधु लिमये : मैं जानना चाहता हूं जो ग्रभी ग्रार्टिकिल 15 (4) पढ़ा उसमें ऐंग्लो इंडियन्स का उल्लेख हैं ?

SHRI GOVINDA MENON: Whether this protection should be extended to Anglo-Indian community or not is a matter of opinion; it is not a matter of law and nor is it a matter of Constitution.

SHRI MADHU LIMAYE: The question is: are they educationally and socially backward?

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): What is your opinion?

SHRI GOVINDA MENON: In 1949 when the Constitution was enacted, the Constituent Assembly was of the opinion that the Anglo-Indian community should be given two seats

by nomination in the Lok Sabha. That was the opinion of the Constituent Assembly. Ten years later, the Government of India formed the same opinion and extended it further. Now it is the opinion of the Government of India and, I hope, of this Parliament that the Anglo-Indian munity deserve to get this reservation for a further period of years. That is why the Bill is here. This is not a matter which can tested by abstract principles contained in any of the articles in III of the Constitution. It is a question of opinion and fact. The Government's opinion, after due deliberation and investigation, is that the Anglo-Indian community, because of its peculiar position in India, deserves to have this reservation for a further period of ten years.

SHRI A. S. SAIGAL: He should describe as to what he found in the investigation.

श्री मधु लिसये : मेरे प्रन्न का उत्तर नहीं द्वाया । मैंने कहा था कि जो भी कानून ग्रायेगा वह अगर किसी मौलिक हक्कों से फंडामेंटल राइट से टकराता है तो वह गलत हैं । उन्होंने कहां यह श्रीपीनियन का सवाल है मैंने पूछा क्या ग्राप कह सकते हैं कि ऐंग्लो इंडियन सामाजिक ग्रार शैक्ष-िएक दृष्टि से पिछड़े वैकवर्ड हैं ? ग्रागर ये कहेंगे कि वैकवर्ड हैं तो मैं बैठ आऊंगा ।

SHRI GOVINDA MENON: That is why Government has brought the Bill for extension of the period. The Anglo-Indian community does not consist of only Mr. Frank Anthony and Mr. Barrow. There are thousands of people who are socially backward in that community.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI GOVINDA MENON: I introduce the Bill.